चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रुई निर्यात में वृद्धि

*158. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रुई के निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) किन-किन देशों को रुई निर्यात की जा रही है और रुई की खरीद और निर्यात किन एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है ;

(ग) उत्पादकों से रुई किस दर पर खरीदी जा रही है ;

(घ) क्या उत्पादन लागत को देखते हुए इसका खरीद मूल्य बहुत कम है;

(ङ) क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में रुई उत्पादक संकट का सामना कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार रुई उत्पादकों को सहायता करने के लिए रुई का खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार चालू रुई वर्ष (सितम्बर 1988–अगस्त 1989) के दौरान रुई की 2.01 लाख गांठें निर्यात के लिए पहले ही रिलीज कर चुकी हैं जबकि पिछले वर्ष केवल 0.05 लाख गांठें रिलीज की गयी थीं।

(ख) रुई का निर्यात बांग्लादेश, बेल्जियम, ताइवान, श्रीलंका, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी (पश्चिम), हांगकांग, जापान, कोरिया (दक्षिण), पोलैंड, थाइलैंड, सिंगापुर, तुर्की आदि को किया जा रहा है। रुई का निर्यात भारतीय रुई निगम, राज्य की एजेन्सियों जैसे कि महाराष्ट्र राज्य सरकारी रुई उपजकर्ता विपणन परिसंघ, मध्य प्रदेश निर्यात निगम, आदि तथा निजी व्यापार क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है।

(ग) रुई उपजकर्ताओं से रुई की खरीद विद्यमान बाजार कीमतों पर की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) इसके बावजूद, चालू रुई वर्ष के दौरान रुई की मुख्य किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतें 50 रुपये से 60 रुपये तक बढ़ा दी गयी थीं तथा रुई वर्ष 1989–90 के लिए उनमें 40 रुपये से 50 रुपये तक और वृद्धि कर दी गई है।

Coca Cola proposal for Noida Export Processing Zone

@*158-A. SHRI CHIMANBHAIMEHTA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Business Standard of 3rd February, 1989 captioned "Three Ministries object to Coca Cola proposal";

(b) whether it is a fact that his Ministry has objected to the Coca Cola proposal for the NOIDA Export Processing Zone; and

(c) if so, what are the reasons for the objection?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Decisions on applications for establishing projects in the Export Processing Zones are taken by Government after consideration by an Inter-Ministerial Committee. It is not the policy of Government to disclose the comments of individual Departments or Ministries received on such proposals.

@Previously Starred Question 199, Transferred from the 8th May, 1989.